

संपादकीय

एकाकी होता जीवन का संध्या काल

सोनीपत, हरियाणा के एक वृद्धाश्रम में रह रहे एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियों और नाती-नातियों में से किसी का अंतिम संस्कार में शामिल न होना केवल एक परिवार की संवेदनाहीनता का मामला नहीं है, बल्कि यह बदलते समाजिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। बेटियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम संस्कार में शामिल होना उचित समझा। विडंबना यह है कि दिवंगत पिता ने अपनी तीनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, उनके विवाह का दायित्व निभाया और जीवन भर परिवार के लिए समर्पित रहे। इसके बावजूद जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें अपनी की मौजूदगी नसीब नहीं हुई। यह घटना समाज को आत्ममंथन के लिए विवश करती है। आज बड़ी संख्या में बुजुर्ग भरा-पूरा परिवार और पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद अकेले जीवन जी रहे हैं। किसी के बच्चे दूसरे शहर या देश में हैं तो किसी के पास समय नहीं है। कई बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या आर्थिक संपन्नता और आधुनिक जीवनशैली हमें उस भावनात्मक जिम्मेदारी से मुक्त कर सकती है, जो माता-पिता के प्रति हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी रही है? आधुनिक जीवन में समय का मूल्य तेजी से बदला है। आज समय को उत्पादकता, करियर और आर्थिक उपलब्धियों से जोड़कर देखा जाने लगा है। प्रत्येक गतिविधि का मूल्यकन इस आधार पर होने लगा है कि उससे कितना लाभ मिलेगा। ऐसे में अंतिम संस्कार जैसी पारिवारिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां कई लोगों की प्राथमिकता सूची में पीछे चली जाती हैं। लेकिन माता-पिता के जीवन का मूल्य किसी आर्थिक गणित से तय नहीं किया जा सकता। जिस पिता ने अपने बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य के लिए अपना जीवन लगा दिया, उसके अंतिम समय में कुछ घंटे निकालना यदि कठिन लगने लगे तो यह केवल व्यस्तता नहीं, हमारी प्राथमिकताओं में आए बदलाव का संकेत है। भौगोलिक दूरी से भी अधिक खतरनाक भावनात्मक दूरी है। जब बच्चे लंबे समय तक माता-पिता से मिलते-जुलते नहीं हैं, बातचीत केवल औपचारिक फोन कॉल तक सीमित हो जाती है, तो रिश्तों में धीरे-धीरे भावनात्मक गर्माहट कम होने लगती है। फिर किसी प्रियजन की मृत्यु भी कई बार गहरी संवेदना के बजाय एक सूचना बनकर रह जाती है। पहले माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होना सामाजिक रूप से गंभीर माना जाता था। संता को अपराध-बोध होता था और समाज भी ऐसे व्यवहार को सहजता से स्वीकार नहीं करता था। आज 'व्यस्तता' और 'विवशता' के नाम पर ऐसी संवेदनाहीनता को सामान्य बनाने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हुआ है। शिक्षा, रोजगार और शहरीकरण ने लोगों को बेहतर अवसर दिए, लेकिन इसके साथ परिवारों के बीच भौगोलिक दूरी भी बढ़ी। एकल परिवारों में पति-पत्नी दोनों के नौकरी करने की स्थिति में बुजुर्गों की देखभाल एक चुनौती बन गई है। कई परिवारों में वृद्धाश्रम को व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जाने लगा है। अक्सर बच्चों में बच्चों की ओर से निर्ममता गुलाकत और फोन का आवासन दिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे मुलाकातों का अंतर बढ़ता जाता है और बातचीत भी औपचारिक होती जाती है। अंततः बुजुर्ग अपने ही परिवार के जीवन से अलग-थलग पड़ जाते हैं। बुजुर्गों की उपेक्षा को केवल आर्थिक समस्या मानना उचित नहीं होगा।

संपन्न परिवारों में भी बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा और भावनात्मक अभाव का सामना कर रहे हैं। वास्तविक संकट बदलती मूल्य-चेतना का है, जिसमें व्यक्ति की उपयोगिता को उसके आर्थिक योगदान से मापा जाने लगा है। बाजार आधारित जीवनशैली ने स्त्री और पुरुष दोनों को लगातार काम, प्रतिस्पर्धा और उपभोग के चक्र में बांध दिया है। इसका प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ा है। बेटियां भी आज शिक्षा और रोजगार के कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसे केवल बेटियों की संवेदनाहीनता के रूप में देखना समस्या को बहुत सीमित कर देना होगा। मूल प्रश्न यह है कि आधुनिक जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक संबंधों के लिए स्थान कितना बचा है। यह सोच बदलने की आवश्यकता है कि बुजुर्ग परिवार पर बोझ हैं। वे अनुभव, परंपरा और पारिवारिक स्मृतियों के वाहक होते हैं। बच्चों के संस्कार और परिवार की निरंतरता में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि वृद्धाश्रम किसी जरूरतमंद बुजुर्ग के लिए सुखी और देखभाल का माध्यम बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब वृद्धाश्रम परिवार की जिम्मेदारी से बचने का साधन बन जाए। बुजुर्गों को सुविधा देना और उन्हें भावनात्मक रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषताओं में परिवार संस्था रही है। बदलते समय में परिवार का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसके भीतर प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और संवेदना जैसे मूल्यों का समाप्त होना समाज के लिए गंभीर खतरा होगा। परिवारों में संवाद और साथ का वातावरण मजबूत करने की जरूरत है। सामाजिक संगठनों की ओर से परिवार और बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को केवल सफलता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी सिखाना होगा कि जीवन में माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का क्या महत्व है। यदि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों को अकेला छोड़ देगी तो कल वही व्यवहार अपाणी पीढ़ी के सामने भी लौट सकता है। यह एक ऐसा सामाजिक दुष्पंथ है, जिसे समय राहते रोकना होगा। सोनीपत की घटना इसलिए झकझोरती है क्योंकि वह हमें भविष्य का आईना भी दिखाती है। तकनीक वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार दिखा सकती है, लेकिन वह उस आत्मीय स्पर्श की जगह नहीं ले सकती, जिसकी जरूरत जीवन के अंतिम क्षणों में होती है। आधुनिकता जरूरी है, लेकिन संवेदनाहीनता उसकी कीमत नहीं हो सकती। समाज की प्रगति तभी सार्थक होगी, जब उसके सबसे बुजुर्ग सदस्य भी अपने जीवन की संध्या में स्वयं को अकेला और अनावश्यक महसूस न करें।

असहमति पर ‘दिमागी नक्सल’ का ठप्पा



अवनीश कुमार गुप्ता

भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा केवल शब्दों का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह समाज के सार्वजनिक वातावरण को प्रभावित करती है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द प्रशासनिक संस्थाओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज और आम जनता की सोच पर असर डालते हैं। इसलिए जब किसी राजनीतिक असहमति, विचारधारा या सरकार की आलोचना के संदर्भ में 'दिमागी नक्सल' जैसा शब्द सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनता है तो इसे महज राजनीतिक बयान मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। इस शब्द के राजनीतिक अर्थ, संवैधानिक सीमाओं और लोकतांत्रिक प्रभाव पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल के बाद देश में राजनीतिक बहस तेज हुई। सत्ता पक्ष की दृष्टि में यह उन वैचारिक प्रवृत्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है जो देश की एकता, विकास और सुखी के विरुद्ध वातावरण बनाती हैं। विपक्ष और आलोचकों ने इसे सरकार से असहमति रखने वालों को बदनाम करने वाली भाषा बताया। इस विवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत इस समय युवाओं के आंदोलनों, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, कथित प्रत्यक्ष लोक

और शासन की जवाबदेही जैसे मुद्दों से भी जुड़ा रहा है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और राष्ट्रविरोधी गतिविधि को एक ही श्रेणी में रखना गंभीर भूल होगा। भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है, हालांकि ये अधिकार युक्तिसंगत संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन हैं। अर्थात् नागरिक को सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली कसौटी इसी सीमा को स्पष्ट रखने में है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरें में डालने वाली गतिविधियों से संबंधित है। इसमें अत्याचारवादी गतिविधियों, शस्त्र विद्रोह तथा ऐसी गतिविधियों को उकसाने वाले क्लृप्तों को गंभीर अपराध माना गया है। लेकिन कानून की व्याख्या सरकार की नीतियों अथवा प्रशासनिक कदमों की वैधानिक माध्यम से आलोचना को स्वतः इस अपराध की श्रेणी में नहीं रखती। यही अंतर लोकतांत्रिक विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का विरोध करना और देश के विरुद्ध हिंसक गतिविधि करना समान नहीं है। हालांकि युवा आंदोलनों ने इस प्रश्न को और प्रसंगिक बनाया है। परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और सरकारी जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बाद पुलिस कार्रवाई तथा प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए। मामलों की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की। यह कदम इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि विवादित घटनाओं का अंतिम फैसला राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र जांच और प्रमाणों से निकाला जाना चाहिए। यदि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, पुलिस पर हमला

किया या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि सुखी बलों ने आवश्यकता से अधिक या अनुपातहीन बल का इस्तेमाल किया तो उसकी भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। लोकतंत्र में कानून की विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब उसकी कसौटी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कृत्य और उपलब्ध साक्ष्य हों। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब राजनीतिक बहस में व्यक्ति के कृत्य से अधिक उसके विचार और पहचान को निशाना बनाया जाता है। 'दिमागी नक्सल' जैसा शब्द यदि वास्तविक हिंसक उग्रवाद और सामान्य राजनीतिक असहमति के बीच अंतर मिटाने लगे तो सार्वजनिक विमर्श अधिक स्पष्ट होने के बजाय अधिक ध्रुवीकृत हो सकता है। किसी व्यक्ति के विचार सरकार को अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन केवल अप्रिय विचार किसी आपराधिक कृत्य का प्रमाण नहीं होते। भारत में विश्वविद्यालयों, मीडिया, नागरिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों की भूमिका इसी कारण महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल चुनाव और संसद तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों में उठने वाले प्रश्न, पत्रकारों की पड़ताल, नागरिक समाज की आलोचना और युवाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक चेतना के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। युवाओं की प्रत्येक मांग सही हो, यह आवश्यक नहीं; लेकिन उनकी प्रत्येक मांग को सुनना और तथ्यों के आधार पर उत्तर देना शासन की जिम्मेदारी अवश्य है। इसी के साथ लोकतांत्रिक चेतना के जिम्मेदारी भी कम नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या सुरक्षा बलों पर हमला किसी लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी आंदोलन का उद्देश्य कितना भी बंध क्यों न हो, हिंसक रास्ता उसकी नैतिक और लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करता है।

इसलिए सरकार को संयम और प्रदर्शनकारियों को अनुशासन—दोनों की आवश्यकता है। संसद की कार्यवाही भी इसी व्यापक संवाद-संकट का संकेत देती है। हालांकि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव तथा व्यवधानों के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षित चर्चा प्रभावित हुई। संसद का मूल उद्देश्य ही असहमति को बहस में बदलना है। यदि संसद पर आंदोलन और संसद के भीतर व्यवधान दोनों बढ़ते जाएं तो यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि संस्थागत संवाद की कमजोर होती क्षमता का संकेत भी माना जाना चाहिए। सत्ता पक्ष को समझना होगा कि आलोचना लोकतंत्र की बीमारी नहीं है। सरकार की नीतियों की समीक्षा, प्रशासनिक निर्णयों पर प्रश्न और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही मांगना नागरिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। दूसरी ओर विपक्ष को भी यह स्वीकार करना होगा कि हर सखसी निर्णय को लोकतंत्र-विरोधी बताना उतना ही नुकसानदेह है। लोकतांत्रिक राजनीति में आरोप से अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण और नारे से अधिक महत्वपूर्ण नीति-विमर्श है। राष्ट्रवाद को भी सरकार और विपक्ष को बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए समझना होगा। राष्ट्र केवल वर्तमान सरकार का नाम नहीं है। राष्ट्र संविधान, नागरिकों, संस्थाओं, विविध सामाजिक-सांस्कृतिक और साझा भविष्य का व्यापक रूप है। कोई नागरिक सरकार की किसी नीति का विरोध करते हुए भी देश और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रख सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय सुखी के नाम पर वास्तविक खतरों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यदि कोई संगठन सचमुच हिंसक उग्रवाद, शस्त्र विद्रोह या अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न है तो राज्य को कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई का आधार राजनीतिक लेबल नहीं, प्रमाण और कानून होना चाहिए। 'दिमागी नक्सल' विवाद इसलिए केवल एक शब्द का विवाद नहीं है। यह उस बड़े प्रश्न से जुड़ा है कि

भारत अपने असहमत नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है। क्या आलोचना का उत्तर तर्क से दिया जाएगा या राजनीतिक ठप्पे से? क्या हिंसक गतिविधि और वैचारिक असहमति के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाएगा? क्या पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारी हिंसा दोनों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या संसद जनता के असंतोष को लोकतांत्रिक संवाद में बदलने की अपनी भूमिका निभाएगी? लोकतंत्र की शक्ति सर्वसम्मति में नहीं, असहमति को संभालने की क्षमता में होती है। मजबूत लोकतंत्र वह नहीं जिसमें हर नागरिक सत्ता की प्रकृसा करे, बल्कि वह है जिसमें नागरिक कठिन प्रश्न पृष्ठ संकेत और सरकार उन प्रश्नों का तथ्यपूर्ण उत्तर देने के लिए तैयार रहे। यदि कोई आरोप गलत है तो तथ्य उसे गलत सिद्ध कर सकते हैं; यदि कोई नीति सही है तो उसके परिणाम उसका बचाव कर सकते हैं; और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कानून तोड़ता है तो न्यायिक प्रक्रिया उसके विरुद्ध कार्रवाई का रास्ता तय कर सकती है। इसलिए भारत को ऐसी राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता हो, लेकिन शांतिपूर्ण असहमति के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक स्थान भी हो। सरकार को आलोचना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं और नागरिकों को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं। संस्थाओं को निष्पक्ष रहना होगा, संसद को संवाद का मंच बनना होगा और राजनीतिक दलों को शब्दों की जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकेत वह नहीं जब नागरिक सरकार से प्रश्न पूछते हैं। वास्तविक संकट तब शुरू होता है जब नागरिक प्रश्न पूछने से डरने लगते हैं। राजनीतिक उद्देश्य क्षणिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को स्थायी शक्ति संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं, प्रमाण आधारित सार्वजनिक विमर्श और असहमति के सम्मान से मिलती है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा इसी संकलन से होगी कि राष्ट्र की सुखी भी सुरक्षित रहे और नागरिक की आवाज भी।

मणिपुर में क्यों तेज हो रहा ‘नो एनआरसी, नो जनगणना’ आंदोलन?

मणिपुर में वर्ष 2027 की प्रस्तावित जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। 'नो एनआरसी, नो सेंसस' के नारे के साथ शुरु हुआ यह आंदोलन अब केवल जनगणना रोकने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे विस्थापन, जनसंख्या में बदलाव, भूमि अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर मुद्दे भी जुड़े हैं। जातीय हिंसा से लंबे समय से प्रभावित मणिपुर में इस आंदोलन ने राज्य सरकार के साथ केंद्र की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्रों में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में बंद, प्रदर्शन और सरकारी गतिविधियों के बहिष्कार की घोषणा से प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। आंदोलन के केंद्र में राज्य के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है। हिंसा के कारण हजारों लोग अपने मूल स्थानों से विस्थापित होकर राहत शिविरों या दूसरे क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में आंदोलनकारी संगठनों का सवाल है कि यदि जनगणना के दौरान विस्थापित लोगों की गणना उनके वर्तमान स्थान पर

होती है तो क्या इससे राज्य की वास्तविक जनसंख्या संरचना सामने आ पाएगी? मसलन, यदि किसी क्षेत्र से विस्थापित परिवार दूसरे जिले में राहत शिविर में रह रहा है तो जनगणना में उसका वर्तमान निवास दर्ज होगा। इसी तरह दूसरे समुदाय के विस्थापित परिवार भी अपने मूल क्षेत्र से अलग स्थान पर रह सकते हैं। आंदोलनकारियों का तर्क है कि हिंसा और विस्थापन से बदले अस्थायी भूगोल को जनसंख्या के स्थायी स्वरूप का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। जनगणना के आंकड़े भविष्य में विकास योजनाओं, संसाधनों के आवंटन, परिसीमन, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे विषयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारी पहले नागरिकों की पहचान और स्थायी जनसांख्यिकीय स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए एनआरसी और जनगणना के बीच अंतर समझना जरूरी है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की आबादी की गणना करना और उससे जुड़ी सामाजिक-आर्थिक जानकारी जुटाना है। वहीं एनआरसी का संबंध नागरिकों की पहचान और नागरिकता के निर्धारण से जुड़ा है। आंदोलन समर्थकों का

तर्क है कि जनगणना से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य में वैध नागरिक आबादी कौन है। इसके बाद जनगणना के आंकड़ों को भविष्य की प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों का आधार बनाया जाना चाहिए। मणिपुर में एनआरसी की मांग नहीं है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। राज्य जनसंख्या आयोग का गठन भी जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़ी चिंताओं के बीच हुआ था। हालांकि विवाद का एक प्रमुख बिंदु कट-ऑफ वर्ष को लेकर है। कई नागरिक संगठनों की मांग है कि 1951 को आधार वर्ष माना जाए। दूसरी ओर, इनर लाइन परमिट के संदर्भ में 1961 को मूल निवासी निर्धारण के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। कट-ऑफ वर्ष को लेकर यह मतभेद आंदोलन को राजनीतिक रूप से और संवेदनशील बना रहा है। आंदोलन समर्थक मणिपुर में अलग-अलग दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों की हवाला दे रहे हैं। उनके मुताबिक 1961 में राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 35.04 प्रतिशत और 1971 में 37.52 प्रतिशत रही, जबकि नागरिकों की पहचान और नागरिकता के निर्धारण से जुड़ा है। आंदोलन समर्थकों का

बदलाव की जांच की मांग की जा रही है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि को सीधे अवैध प्रवास का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। जनसंख्या में बदलाव के पीछे प्राकृतिक वृद्धि, आंतरिक प्रवासन, विस्थापन और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष के लिए प्रमाण आधारित जांच जरूरी है। मणिपुर की म्यांमार से लगती सीमा के कारण अवैध प्रवास का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। इसी वजह से एनआरसी की मांग को लेकर बहस और अधिक संवेदनशील हो जाती है। हालांकि कुकी-जो समुदाय और म्यांमार के चिन समुदायों के बीच जातीय और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। ऐसे में किसी पूरे समुदाय को अवैध प्रवासी मान लेना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है, बल्कि पहले से जातीय तनाव से गुजर रहे राज्य में अविश्वास की भी बढ़ा सकता है। इसलिए नागरिकता और प्रवास से जुड़े मामलों का निर्धारण व्यक्तिगत दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर होना जरूरी है। 'कैपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन' के नेतृत्व में आंदोलन ने हाल में जोर पकड़ा। 48 घंटे के बंद के दौरान घाटी के कई जिलों में सड़कें बाधित

रहीं और प्रदर्शन किए गए। मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले भी जलाए गए। आंदोलन में छात्रों और महिलाओं की भागीदारी ने इसे व्यापक स्वरूप दिया है। संगठनों की ओर से सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार की घोषणा भी की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखने की बात कही गई है। बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को तीन दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया। वर्ष 2027 की जनगणना अब इस पूरे विवाद का तत्काल केंद्र बन गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने का काम और बाद में जनसंख्या तथा सामाजिक-आर्थिक विवरण जुटाने की प्रक्रिया होगी है। इसी बीच कुछ क्षेत्रों में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रद्द होने से प्रशासनिक तैयारियों पर भी असर पड़ा है। सवाल यह है कि जब एनआरसी और जनगणना को लेकर संगठनों की आपत्तियां पहले से सामने आ रही थीं तो सरकार और आंदोलनकारी समूहों के बीच व्यापक राजनीतिक संवाद पहले क्यों नहीं शुरू हो सका।

नीरज कुमार दुबे

कूल्हों की जकड़न और तनाव दूर करने में मददगार है ‘एका पाद राजकपोतासन’

आधुनिक जीवनशैली में लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी और लगातार बढ़ता तनाव शरीर पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। खासकर लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने से कूल्हों, जांघों और कमर के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में योग शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का प्राकृतिक माध्यम हो सकता है। योग के विभिन्न आसन में 'एका पाद राजकपोतासन' को कूल्हों और शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। यह एक उन्नत स्तर का योगासन है, जिसमें कूल्हों के जोड़, जांघों और रीढ़ पर काम होता है। सही विधि, नियंत्रित श्वास और प्रशिक्षित मार्गदर्शन के साथ इसका अभ्यास शरीर को अधिक लचीला बनाने तथा मन को शांत रखने में सहायक हो सकता है। 'एका पाद' का अर्थ एक पैर, 'राज' का अर्थ श्रेष्ठ, 'कपोत' का अर्थ कबूतर और 'आसन' का अर्थ मुद्रा होता है। इसकी अंतिम मुद्रा कबूतर जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे राजकपोतासन कहा जाता है। आयुष्य मंत्रालय के अनुसार, एका पाद राजकपोतासन उन्नत स्तर का योगासन



है। यह कूल्हों के जोड़ और रीढ़ की कलम पर काम करने वाला आसन है तथा इसमें पीछे की ओर झुकने की मुद्रा भी शामिल होती है। नियमित अभ्यास शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के साथ एकाग्रता तथा मानसिक शांति में भी सहायक हो सकता है। दिनभर बैठकर काम करने वाले लोगों में कूल्हों और उनके आसपास की मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना आम है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से शरीर की गतिशीलता में कमी आ सकती है। एका पाद राजकपोतासन में कूल्हों को खोलने और जांघों के आगे वाले हिस्से में खिंचाव पैदा करने वाली मुद्रा बनती है। इसके अभ्यास से कूल्हों, रीढ़, लुट्सर यानी लंबावों तथा पैरों की मांसपेशियों में निचलापन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस आसन में शरीर को

बढ़ा सकता है। ऐसे में नियमित योगाभ्यास शरीर को सक्रिय रखने के साथ मानसिक रूप से भी राहत देने में सहायक हो सकता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि कूल्हों में जमा तनाव या नकारात्मक भावनाएं केवल किसी एक आसन से दूर हो जाती हैं। मानसिक तनाव के लिए पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित जीवनशैली और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह भी महत्वपूर्ण हैं। इस आसन को करते समय शरीर को धीरे-धीरे मुद्रा में लाना चाहिए। शुरुआत में इसे प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में करना बेहतर है। पहला चरण: सबसे पहले योग मैट पर आरामदायक स्थिति में आएँ और शरीर को तैयार करें। पारंपरिक क्रम में नीचे की ओर मुख किए हुए आसन से पैर को आगे लाकर मुद्रा में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा चरण: दाहिने पैर को आगे लाकर घुटने को मोड़ें और दाहिनी जांघ तथा पैर को मैट पर सहज स्थिति में रखें। तीसरा चरण: बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। दोनों कूल्हों को यथासंभव सामने की ओर समान स्थिति में रखने का प्रयास करें। चौथा चरण: यदि कूल्हों पर दबाव या असंतुलन महसूस हो तो दाहिने नितंब के नीचे योग ब्लॉक, मुड़ा हुआ कंबल या तिकिया रखा जा सकता है।



मेघ –मेघ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने का है। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा।
वृषभ–वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है, लेकिन जीवसाथी और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। दायित्व जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी।
मिथुन –मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों वाला रह सकता है। छोटी-मोटी चोट लगने या शरीर में किसी तरह की असहजता महसूस होने की आशंका है, हालांकि किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं।
कर्क–कर्क राशि के जातकों को आज भावनाओं में बहकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में आपसी मतभेद या कहासुनी की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य भी पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगा और कुछ मानसिक या शारीरिक परेशानी महसूस हो सकती है।
सिंह–सिंह राशि के जातकों के लिए

संपत्ति और घरेलू मामलों के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। हालांकि घर-परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद की स्थिति भी बन सकती है।
कन्या–कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और प्रगति के संकेत दे रहा है। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और कामकाज में आपकी सक्रियता रंग ला सकती है।
तुला–तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रह सकता है। आय में बढ़ोतरी के अवसर मिल सकते हैं और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है तथा पुराने संबंधों के साथ नए लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा।
वृश्चिक–वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ देने वाला रह सकता है। नौकरी और रोजगार से जुड़े मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।
धनु–धनु राशि के जातकों का मन आज कुछ परेशान रह सकता है। बिना किसी

स्पष्ट कारण के चिंता या अज्ञात भय महसूस होने की संभावना है। मानसिक दबाव के कारण किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन लग सकता है।
मकर–मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी सकारात्मक रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के साथ पुराने माध्यमों से भी धन प्राप्त होने की संभावना है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
कुंभ–कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज और कानूनी मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। न्यायालय से जुड़े किसी पुराने मामले में सफलता मिलने की संभावना है।
मीन–मीन राशि के जातकों को आज भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। दिन भाग्य का साथ देने वाला रह सकता है, और यात्रा से जुड़े अवसर बन सकते हैं। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं तथा कुछ ऐसे काम भी पूरे हो सकते हैं जिनके लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। प्रेम और व्यापार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक स्थिति बनी रह सकती है।

मण्डी स्थानान्तरित पहल से शहर को जाम एवं भीड़ से राहत, बैठक में व्यापार बंधुओं ने बताया आभार

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देशन में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न व्यापार मण्डलों के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों की समस्याओं को एक-एक कर गंभीरता से सुना गया तथा सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तराण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए।

बैठक में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने शहर में लंबे समय से बनी जाम एवं अत्यधिक भीड़ की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा की गई पहल की सराहना की। व्यापारियों ने सख्ती मण्डी एवं आड़ुतियों की दुकानों को नवीन मण्डी समिति अमरपुर में स्थानान्तरित किये जाने पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश का आभार व्यक्त करते हुए कहा

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने कसा शिकंजा

» खराब प्रगति पर चिकित्साधिकारियों को फटकार

» जननी सुरक्षा, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, आयुष्मान भारत और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की। बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सभी चिकित्सा अधिकारियों को जनपदवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपदवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना



ललितपुर

कि उनके इस निर्णय से शहरवासियों एवं व्यापारियों को जाम और भीड़ की समस्या से काफी राहत मिली है। व्यापारियों ने कहा कि जिलाधिकारी ने अपनी प्रशासनिक इच्छा शक्ति एवं दृढ़ नेतृत्व का परिचय देते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता से लिया है और अपनी पूरी प्रशासनिक टीम को प्रभावी ढंग से लगाया। लंबे समय से चली आ रही शहर की जाम एवं भीड़ की समस्या के समाधान की दिशा में यह कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी के प्रयासों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

बैठक के दौरान जिला महामंत्री अनिज जैन बबड़ी ने अवगत कराया

जांच अधिकारी नामित किया गया था, किन्तु अभी तक जांच आख्या प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही लंबित थी, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे से दूरभाष पर वार्ता की तथा एक सप्ताह में जांचक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जिला महामंत्री अनिल जैन द्वारा व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से बेहतर सुविधाएं एवं योजनाओं का लाभ दिलाने जाने से सम्बंधित प्रस्ताव रखे, इस पर अपर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं शासन द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराया जाए। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित



ललितपुर

सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से योजनावार प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कम प्रगति के कारणों की जानकारी ली।

जननी सुरक्षा योजना के तहत एनसी पंजीकरण कम पाए जाने पर महरीनी के एमओआईसी एवं बीपीएम को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं एनसीडी स्कीमिंग की कम प्रगति पर बिरधा एवं तालबेहट के एमओआईसी को कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर लगातार खराब प्रदर्शन पाए जाने पर जखौरा के एमओआईसी को आगामी दो माह में प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उन्हें प्रशासनिक कार्य से हटया जा सकता है। साथ ही जखौरा के बीपीएम को पूर्व तेजाती स्थल पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान की कम प्रगति

पर संबंधित एमओआईसी एवं बीपीएम को भी कार्य में सुधार की कड़ी चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की ब्लॉकवार प्रगति की भी समीक्षा की। विकासखंड बिरधा, महरीनी, बार एवं जखौरा में अभियान की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अभियान में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मचारियों का मानव्य प्रगति में सुधार होने तक आहरित न करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डा.वीरेंद्र सिंह, डीपीओ नीरज सिंह, बीएसए रलेश कुमार, डीआईओ, डीपीएम डा. रजिया फ़तेज, सभी एमओआईसी, डीएमओ सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।

अपहरण कर बंधक बनाने और जबरन जमीन का बैनामा कराने का आरोप

» अनाथ दलित युवक ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार

» बैंक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने की मांग

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करगन निवासी एक युवक ने कुछ लोगों पर अपहरण कर बंधक बनाने, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देकर उसकी जमीन का जबरन बैनामा कराने तथा बैंक लेनदेन में फर्जीबाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीडित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटना से संबंधित बैंक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने की गुहार लगाई है। ग्राम करगन निवासी ऋषी पुत्र स्व.रामकिशन ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके माता-पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2022 में उसके पितामह की मृत्यु के बाद वह करीब 14 वर्ष की उम्र में संपत्ति का वारिस बना था। वर्तमान में वह डबराकलां में रह रहा है। बताया कि 24 जून 2026 को दोपहर करीब तीन बजे वह गांव में मौजूद था। इसी दौरान रवीन्द्र यादव और बालू यादव ने मोटरसाइकिल पर बैठकर राखनचंपुर ले



गए। आरोप है कि वहां से उसे दैलवारा के पास ले जाया गया और बाद में ख्वासियों गाड़ी में बैठकर एक कमरे में बंधक बना दिया गया। पीडित का आरोप है कि वहान पर प्रधान लिखा था और उसे रामसेवक का पुत्र तिलकराम चला रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने युवक को शराब पिलाई तथा उसके घर पर कट्टा रखकर जान से मारने की धमकी दी। उसका पैना कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिया गया। पीडित के मुताबिक उसे डबराकलां, बिना स्थित निर्मा फैक्ट्री के पास सहित अलग-अलग स्थानों पर करीब चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। पीडित ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए जाने के दौरान उसकी जमीन का उसकी वास्तविक सहमति के बिना बैनामा करा लिया गया। शिकायत के मुताबिक 30 जून 2026 को जमीन का बैनामा जूरी एवं उदल सिंह पुत्रगण तिलकराम, निवासी अमरपुर के नाम करारा गया। पीडित ने बैनामे में भुगतान के तौर पर

दर्शाए गए यूनियन बैंक के चेक संख्या 011925 को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि संबंधित चेक को लेकर बैंक खाते और चेकबुक संबंधी स्थिति संदिग्ध है तथा बाद में बैंक लेनदेन के माध्यम से चेक की राशि रामसेवक के खाते में पहुंचाई गई और भुगतान प्राप्त कर लिया गया। शिकायती पत्र में पीडित ने बैनामे में सुबेन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी नकवानी तथा राकेश पुत्र चंदराम को गवाह बनाए जाने का भी उल्लेख किया है। उसका दावा है कि वह इन कथित गवाहों को जानता तक नहीं है। ऐसे में उसने बैनामे की पूरी प्रक्रिया की जांच करवाए जाने की मांग की है। पीडित ऋषी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करारक दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यूनियन बैंक में संबंधित तिथि के लेनदेन, पहचान और भुगतान से जुड़े सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अभिलेख सुरक्षित करवा जाएं, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।

विज्ञान बस बनी उत्सुकता का केंद्र दूरस्थ क्षेत्रों में कर रही है वैज्ञानिक सोच का विकास



स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के प्रयासों से एवं जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशन में आईआईटी कानपुर एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान बस जनपद में उत्सुकता का केंद्र बनी गई है। इसी क्रम में विज्ञान बस श्री शांति निकेतन इंटर कॉलेज एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को विज्ञान की करीब से समझने के उद्देश्य सहयोगों को जानने का अगुआ अवसर मिला। 'विज्ञान बस' भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन

अवधारणाओं को प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से सरल एवं रोचक ढंग से समझाया।

विज्ञान बस में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रयोगों में सहभागिता की और विज्ञान से जुड़े सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कस्तूरबा गांधी की प्रधानाचार्या आरती ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से छात्राओं के जिज्ञासु मन में उठ रहे प्रश्नों को प्रयोगात्मक तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है। इस दौरान जिला विज्ञान क्लब समन्वयक राहुल जैन, प्रधानाचार्य लक्वुश यादव, शिक्षक सूर्यबली, सुदीपन, प्रगति पाण्डेय, अफरीन सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बनी निराश्रित बच्चों का सहारा

ललितपुर में 1773 लामार्थी योजना से जुड़े, 911 बच्चों को मिली पहली किस्त की आर्थिक मदद

ललितपुर। जिले में निराश्रित एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहारा बन रही है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की संवेदनशीलता और जिला प्रशासन की पहल से पात्र बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दोनों घटकों के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिला प्रशासन के अनुसार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 120 पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 27 लाख 12 हजार रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत जिले में 1653 लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 791 पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 58 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन ने योजना के सभी लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निदेश जारी किए हैं। शासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आधार बेस्ट पेमेंट प्रक्रिया लागू की जा रही है। ऐसे में लाभार्थियों को अपने बाक-बालिकाओं के आधार कार्ड से संबंधित बैंक खाते में डीबीटी/एनपीसीआई कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित बैंक खाते में डीबीटी/एनपीसीआई नहीं कराया गया तो लाभार्थी योजना की धनराशि से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। सभी लाभार्थियों को बैंक में डीबीटी/एनपीसीआई की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद इसकी सूचना जिला प्रवेशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक 318 लाभार्थियों द्वारा डीबीटी/एनपीसीआई कराया जा चुका है। शेष लाभार्थियों से भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें योजना की आर्थिक सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला प्रशासन का उद्देश्य योजना का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद बच्चों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर एवं निराश्रित बच्चों की शिक्षा, पालन-पोषण और बेहतर भविष्य की दिशा में उन्हें आवश्यक सहायता मिल सके।

श्रावण मास में श्री किले के हनुमान मंदिर में मासपारायण, उमड़ रहे श्रद्धालु

महरीनी। पावन श्रावण मास के अवसर पर महरीनी नगर स्थित श्री 1008 किले के हनुमान मंदिर प्रांगण में मानस प्रचारिणी समिति के तत्वावधान में प्रतिदिन मास पारायण का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मासपारायण के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहता है। श्रद्धालु सामूहिक रूप से धार्मिक पाठ में शामिल होकर भगवान श्री राम एवं हनुमान जी को आराधना कर रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक चेतना के साथ समाज में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं को मजबूत करना है। आयोजन को सफल बनाने में सुखचंदन तिवारी, रामकृष्ण नायक, हरदेव रावत, बाबूलाल नायक, जगदीश बिस्नेर, ओमप्रकाश पालीवाल, शिव प्रसाद पुरोहित, रमेशचंद्र पांडेय, कृष्ण स्वरूप पटेरिया, बलराम पुरोहित, कैलाश नारायण सिसोदिया, ओमप्रकाश साहू, रामेश्वर प्रसाद सोनी, महिलाल सिंह, गणेश प्रसाद साहू, पं. विनोद पुरोहित, हर्ष सोनी, देवांश सोनी, सुरेश सहित अनेक श्रद्धालुओं का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

आज ललितपुर आएंगे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी

विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा

ललितपुर। प्रभारी मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी शनिवार 22 अगस्त को ललितपुर के दौरे पर आएंगे। अपने भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री जिले में चल रही विकास परियोजनाओं एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री सुबह 9.55 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। सुबह 9.55 से 10.25 बजे तक लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 10.25 से 10.55 बजे तत्प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति एवं कोर कमिटी की बैठक आयोजित होगी। बैठक में जिले से संबंधित प्रशासनिक एवं विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। प्रभारी मंत्री सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान जिले में संचालित विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष बनीं बसंती लारिया

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में ललितपुर जिले में नई जिम्मेदारी सौंपी है। एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पीयूष राय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. शर्मा की अनुमति एवं संगठन के अनुमोदन के बाद साईं सर्वश्रेष्ठ भारत गैस की संचालक श्रीमती बसंती लारिया को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) का ललितपुर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन की ओर से जारी नियुक्ति अधिसूचना में बसंती लारिया को ललितपुर जिले में संगठन की गतिविधियों को गति देने तथा एलपीजी वितरकों को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी गैस एजेंसी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) से संबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष पीयूष राय ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष से अपेक्षा की है कि वह संगठन की नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए जिले के एलपीजी वितरकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाएंगी और उनके हितों



की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगी। साथ ही निर्धारित अवधि में ललितपुर जिले की कार्यकारिणी का गठन कर इसकी सूचना प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बसंती लारिया ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि ललितपुर जिले के सभी एलपीजी वितरकों को साथ लेकर उनकी समस्याओं के समाधान, अधिकारों एवं हितों की रक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। बसंती लारिया जिलाध्यक्ष मनोनीत होने और एलपीजी वितरकों, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों तथा शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सिद्धनपुरा में चार सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन



» हर वार्ड तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : सोनाली जैन

» विकास कार्य पूरे होने से आवागमन सुगम होगा, जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

नगर पालिका परिषद की ओर से नगर के समग्र एवं संतुलित विकास को गति देने के लिए विभिन्न वार्डों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को वाई नंबर-01 के मोहल्ला सिद्धनपुरा में चार सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। नपाध्यक्ष सोनाली जैन ने वाई पार्षद सोनसिंह यादव के साथ पूजा-अर्चना कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के दौरान क्षेत्रवासियों में खालसा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद नागरिकों ने नपाध्यक्ष एवं वाई पार्षद का पुष्पमालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कराए जाने पर पालिका प्रशासन का आभार जताया। नागरिकों ने बताया कि लंबे समय से सड़क और जल निकासी की समस्या को नगरा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के

बाद आवागमन सुगम होने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से भी राहत मिलने की उम्मीद है। नपाध्यक्ष ने कहा कि नगर का प्रत्येक वार्ड उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक तक बेहतर आधारभूत सुविधाएं पहुंचाना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण कार्य करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना लक्ष्य है, जिससे नागरिकों का जीवन सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इससे जलभराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने में मदद मिलेगी। जनता ने जिस विश्वास के साथ नगर की सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास को बनाए रखते हुए विकास कार्य पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराए जा रहे हैं। कहा कि आने वाले समय में भी नगरहित को सर्वोपरि रखते हुए स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित एवं आधुनिक ललितपुर के निर्माण के लिए विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि नगर के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर विकास को इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में वाई पार्षद सोनसिंह यादव, प्रभारी सफाई निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त लिपिक रमाकान्त तिवारी, नवजुल लिपिक सुधीर रावत, गौरज प्रभारी अमित कुमार, धीरेन्द्र धावरी सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी उपस्थित रहे।

विद्यालयों में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा को लेकर जागरूकता प्रशिक्षण

600 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया प्रशिक्षण

स्वतंत्र प्रभात | ललितपुर

जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देश के क्रम में स्कूल सेप्टी प्रोग्राम के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता प्रशिक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं विद्यार्थ्य स्टाफ को आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से बचाव एवं राहत कार्य करने के लिए परिश्रित करना तथा विद्यालयों को आपदा के प्रति सुरक्षित एवं तैयार बनाना रहा। इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में एवं सरस्वती मंदिर महाविद्यालय में विशेष जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में लगभग 600 छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को आपदाओं के प्रभावों से प्रतिभाषा किया। प्रशिक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को भूकंप, आगजनी सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के समय क्या करें और क्या न करें, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक बचाव एवं आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही



दामिनी एवं सचेत ऐप के उपयोग तथा विभिन्न माध्यमों से मौसम एवं आपदा संबंधी चेतावनियों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति को प्रशिक्षित करते हुए विद्यालय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करने, आपदा की स्थिति में जिम्मेदारियां निर्धारित करने तथा छात्र-छात्राओं की विशेष टीम गठित कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। फायर सेप्टी एवं अन्य आपदा सुरक्षा उपायों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को सीपीआर (CPR) की उपयोगिता एवं आपात स्थिति में इसके सही तरीके से प्रयोग के संबंध में व्यावहारिक जानकारी दी गई, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राजीव गांधी की जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, मरीजों को बांटी होम्योपैथिक दवाएं

स्वतंत्र प्रभात | महरीनी

पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को जैन होम्योपैथिक के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कांफ्रेंस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. विक्रम बहादुर जैन ने मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनीं और आवश्यक जांच के साथ चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया।

लोधी महासभा ने श्रद्धापूर्वक मनाई बाबू कल्याण सिंह की पुण्यतिथि



करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने समाज में शिक्षा, जागरूकता और एकजुटता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि बाबू कल्याण सिंह का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लोधी महासभा जिलाध्यक्ष शिक्षक सतर सिंह लोधी, जोधन सिंह लोधी, मुनालाल राजपुत, धनीराम

सिंह राजपुत करौदा, देशराज सिंह, फूल सिंह, सुधीर सिंह, कुंजज सिंह, निर्मल सिंह भौति, डॉ. नरेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, यशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, लाल सिंह, कुमाल सिंह, मुनायाम सिंह सहित नगर एवं क्षेत्र के दर्जनों सामाजिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक भरत सिंह लोधी ने किया, जबकि मुनालाल राजपुत ने सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

साक्षिप्त खबरें

भगवत प्रसाद शुक्ल की पुण्यतिथि पर अर्पित हुई पुष्पांजलि



लालगंज, प्रतापगढ़। नगर के धघुआ गाजन स्थित आइन्स्टीन पब्लिक स्कूल के सभागार में गुरुवार की शाम समाजसेवी एवं शिक्षामनोषी पं० भगवत प्रसाद शुक्ल की आठवीं पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनायी गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान की निदेशिका श्रुति शुक्ला एवं संरक्षक विभवभूषण शुक्ल ने स्व० शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों तथा अभिवाक्कों ने भी विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय भगवत प्रसाद शुक्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित किये। कार्यक्रम में बोलते हुए निदेशिका श्रुति ने कहा कि स्व. भगवत प्रसाद शुक्ल ने सादगीपूर्ण जीवन के साथ शैक्षिक एवं सामाजिक सरोकार को नई दिशा दी। विशिष्ट अतिथि डॉ० सौरभ मिश्र रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक विभवभूषण शुक्ल व संयोजन प्रधानाचार्य शुभ्रांशु सिंह ने किया। संचालन उप प्रधानाचार्य आनंदे डिसिल्वा ने किया। इस मौके पर योगेन्द्र शुक्ला, महेंद्र पाठक, गरिमा मिश्रा, देवेन्द्र मिश्र आदि रहे।

उन्नाव में 16 घंटे बिजली गुल, आक्रोशित लोगों ने लाइनमैन को बनाया बंधक



उन्नाव। मिश्रा कॉलोनी में करीब 16 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों का सब्र टूट गया। गुरुवार रात आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे लाइनमैन को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। जानकारी के अनुसार, मिश्रा कॉलोनी में गुरुवार सुबह से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की ओर से नया ट्रांसफार्मर भेजा गया, लेकिन वह भी खराब निकला। इससे आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। लगातार 16 घंटे तक बिजली न आने से उमस और गमी में लोग बेहाल हो गए। रात करीब 11 बजे बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे लाइनमैन को लोगों ने घेर लिया और बंधक बना लिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार कई घंटे तक बिजली न आने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बाद भी आपूर्ति बहाल न होने से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। शुक्रवार तक भी कॉलोनी की बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। वहीं इस संबंध में एक्सपर्ट ने भारत गौतम ने बताया कि प्रकरण उसके संज्ञान में है। मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

ड्यूटी से वंचित पीआरडी स्वयंसेवकों को आवेदन का अंतिम मौका

31 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन, इसके बाद नहीं मिलेगा अवसर
उन्नाव। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने ऐसे पीआरडी स्वयंसेवकों को अंतिम अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने विभाग की ओर से समय-समय पर आयोजित 22 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और जिनका नाम जनपद के नॉमिनल रोल रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन विभागणी पोर्टल पर नाम फीड न होने के कारण ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार ऐसे सभी पीआरडी स्वयंसेवक 31 अगस्त 2026 तक विकास अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर नाम दर्ज न होने के कारण ड्यूटी से वंचित स्वयंसेवकों को यह अंतिम समयबद्ध अवसर दिया जा रहा है। विभाग ने जनपद के संबंधित पीआरडी स्वयंसेवकों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है। 31 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ब्लाइंड कर्ट्स चिन्हित, कार्ययोजना तैयार साइनेज और स्पीड ब्रेकर लगेंगे, ओवरलोड वाहनों पर सख्ती

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उन्नाव। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट के पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में ब्लाइंड कर्ट्स को समाप्त करने, दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइनेज व स्पीड ब्रेकर लगाने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, यूपीडीए सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एनएच-27 पर मिले कई ब्लाइंड कर्ट्स समिति ने जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य प्रमुख मार्गों पर ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना संभावित स्थलों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि एनएच-27 सहित कई मार्गों पर ब्लाइंड कर्ट्स चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार



कर शासन को भेजी जा चुकी है। बजट मिलते ही सुधार कार्य शुरू करा दिया जाएगा। **रिफ्लेक्टिव लाइट और टेप लगाने पर जोर** बैठक में कई दुर्घटना संभावित स्थानों पर साइनेज, रिफ्लेक्टिव लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सड़क के दोनों ओर ऐसे कई बिंदु चिन्हित किए गए हैं। इन कार्यों का अनुमानित बजट तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर काम जल्द शुरू कराएं। एनएचएआई की टीम को निर्धारित स्थलों पर स्पीड ब्रेकर सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा से

जुड़े सभी उपायों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। **ओवरलोड पर डेढ़ से दो करोड़ का जुर्माना** बैठक में ओवरलोड वाहनों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल माह से ओवरलोड के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक ओवरलोड वाहनों पर लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। कार्रवाई के बाद ओवरलोडिंग में कमी आई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा। भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को स्पष्ट संदेश जाए कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महंगाई ने खराब किया रसोई का बजट

सिद्धार्थनगर। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। चीनी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के दामों में अचानक तेजी आने से आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ गया है। सबसे ज्यादा तेजी चीनी के भाव में आई है। 15 दिन पहले 48 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब 62 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पिछले तीन दिनों में ही इसके दाम करीब 10 रुपये किलो बढ़े हैं। 50 किलो के चीनी कट्टे पर भी तीन दिन में करीब 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चीनी के दाम बढ़ने का असर घर की रसोई से लेकर मिठाई की दुकानों तक दिखाई देने लगा है। चाय, मिठाई और त्योहारों पर बनने वाले पकवानों में चीनी का इस्तेमाल कोटी में सदर तहसील क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद करेंगी। अपराह्न 4 बजे रानीगंज कैंप कार्यालय, बभनमई-रामगढ़ में रक्षाबंधन उत्सव में शामिल होंगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धीरज ओझा की सहभागिता रहेगी।

महिला आयोग की सदस्य 25 अगस्त को करेंगी जनसुनवाई व निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा 24 और 25 अगस्त को प्रतापगढ़ के दौर पर रहेंगी। इस दौरान वह महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण, जनसुनवाई और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद के साथ रक्षाबंधन उत्सव में भी शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 अगस्त को अपराह्न 4 बजे महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा कौशाम्बी के भरवारी स्थित कैंप कार्यालय से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होंगी। अपराह्न 5.30 बजे निरीक्षण भवन, प्रतापगढ़ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगी। 25 अगस्त को सुबह 8 बजे आंगनबाड़ी केंद्र का

निरीक्षण करेंगी। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवजात बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाएगा। इसके बाद पूर्वान्ह 9 बजे वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा। पूर्वान्ह 11 बजे मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ पहुंचकर निरीक्षण करेंगी और प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगी। इसके बाद अपराह्न एक बजे विकास भवन में जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। अपराह्न 2 बजे विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद अपराह्न 3.30 बजे अफीम आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा समूहों की महिलाओं से संवाद करेंगी। अपराह्न 4 बजे रानीगंज कैंप कार्यालय, बभनमई-रामगढ़ में रक्षाबंधन उत्सव में शामिल होंगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धीरज ओझा की सहभागिता रहेगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छात्र-छात्राओं के साथ किया संवाद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/प्रशिक्षु आईएएस थनिंगईयरसन टी द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के साथ संवाद एवं करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से उनके करियर लक्ष्यों, उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर विस्तार से संवाद किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली चुनौतियों, तैयारी की रणनीति, समय प्रबंधन एवं निरंतर अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए अनुशासन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ें।

सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम सख्त, ओवरलोडिंग और अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उन्नाव। सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने और जिले की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर आवश्यक स्थानों पर स्पीड लिमिट बोर्ड लगाए जाएं। सड़क सुरक्षा को नगरे लगे सेक्टर, रिफ्लेक्टर और प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाए, ताकि रात के समय हादसों की आशंका कम हो। डीएम ने संपर्गागीय परिवहन अधिकारी को ओवरलोड वाहनों और अवैध परिवहन के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में कहीं से भी ओवरलोडिंग की शिकायत नहीं भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने छात्रों को मोबाइल फोन एवं अनारवश्यक गैजेट्स में समय व्यतीत करने के बजाय खाली समय का सदुपयोग स्पेर्सेट, ग्रुप एक्टिविटी एवं रचनात्मक गतिविधियों में करने के लिए प्रेरित किया। सत्र के अंत में छात्र-छात्राओं ने करियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा सहजता एवं विस्तार से उत्तर देते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने भी छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। संवाद सत्र के उपरांत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का निरीक्षण किया गया। उन्होंने छात्रावास में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई,

भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों के साथ भोजन भी किया तथा भोजन की गुणवत्ता की जांच की। छात्रावास की व्यवस्थाओं को और बेहतर एवं सुव्यवस्थित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थनिंगईयरसन टी को अपने बीच पाकर छात्र-छात्राओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर संवाद बनाए रखने तथा भविष्य में पुनः ऐसे सत्र आयोजित कर मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कॉलेज के डायरेक्टर धनंजय सिंह, चीफ वाइडेन डी.पी. मिश्रा, प्रोफेसर विशाल चंदेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का आभार व्यक्त किया गया।

बारावफात, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न



बिस्कोहर (सिद्धार्थनगर)। आगामी बारावफात, रक्षाबंधन एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बिस्कोहर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम प्रधानों, संध्रांत नागरिकों, जुलूस आयोजकों तथा हिंदू-मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और मौलवियों ने भाग लिया। बैठक मे पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही अत्याधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक प्रभारी निरीक्षक हरेकृष्ण उपाध्याय के नेतृत्व में आयोजित हुई। इस दौरान उपनिरीक्षक तालीमुद्दीन खान, इशाशु श्रीवास्तव, विजय कुमार, इंदरजीत सिंह, आशीष मौर्य, कांस्टेबल अजय यादव बलराम सिंह, अनुज राम त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ, शाहिद अजीज सिद्दीकी, जितेंद्र मौर्या, ताीर मनोज कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संपर्गागीय परिवहन अधिकारी संजीव कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

विद्यालय का ताला तोड़ चोरी की घटना को दिया अंजाम

महराजगंज (ठूठीबारी)। बीती रात को प्राथमिक विद्यालय छोटका टोला भरवलिया में चोरों ने आफिस व किचन रूम का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार की सुबह जब प्रधानाध्यापक विनय राज वर्मा विद्यालय पहुँचे तो आफिस व किचन का ताला टूटा देख होश उड़ गए। तत्काल डायल 112 पर फोन कर चोरी की घटना की जानकारी दी। प्रधानाचार्य विनय राज वर्मा ने बताया कि किचन रूम से एक बंडल थाली (30 पीस) गिलास 30 पीस चम्मच 30 पीस व राशन उठा ले गये। वही 16 जुलाई 2026 को भी चोरों ने किचन का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही न होने से पुनः चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत पुलिस क्षेत्राधिकारी रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल किया जा रहा है।

परिषदीय विद्यालयों में लाइब्रेरी से बढ़ रही पढ़ने की ललक, किताबों से निखर रही बच्चों की प्रतिभा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर और रुचिकर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं। विद्यालयों में संचालित स्कूल लाइब्रेरी एवं लर्निंग कॉर्नर बच्चों के लिए ज्ञान का नया केंद्र बन रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों के साथ कहानी, बाल साहित्य, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों से बच्चों का जुड़ाव बढ़ रहा है। विद्यालयों की लाइब्रेरी में बच्चों की आयु और रुचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। छात्र-छात्राएं अपनी पसंद की किताबें चुनकर उनका नियमित अध्ययन कर रहे हैं। इससे उनमें पढ़ने की आदत विकसित होने के साथ नई चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासा भी बढ़ रही है।

स्टडी कॉर्नर बना बच्चों के आकर्षण का केंद्र विद्यालयों में विकसित किए गए स्टडी कॉर्नर बच्चों को सहज और आकर्षक

सवर्ण आयोग का गठन किया जाय तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण हो-रामलखन सिंह

क्षत्रिय कल्याण परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की प्रतापगढ़ इकाई के जिला अध्यक्ष राम लखन सिंह ने राष्ट्रीय इकाई के निर्देश पर शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ सौंपा। ज्ञापन में केन्द्र सरकार से मांग

की गई है कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाय तथा एससी एसटी एक्ट को पूर्णतया समाप्त किया जाय एवं प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ सभी वर्गों एवं जातियों को समान रूप से दिया जाय। अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपने के उपरान्त उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए ज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर करणी सेना के जिल अध्यक्ष अनुज सिंह, श्याम नारायण सिंह डा. विशाल सिंह, आरबी सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, अमित सिंह रज्जू शिव कुमार सिंह, सैलेश सिंह, शमशेर सिंह, सुरेश बहादुर सिंह, जयसिंह, डब्लू सिंह आदि की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही।अन्त डा. विशाल सिंह ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।



तरीके से अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चे यहां बैठकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा पढ़ी गई कहानियों और विषयों पर शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं। इससे विद्यालयों में पठन-पाठन का सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है।

पठन कौशल के साथ अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार नियमित पुस्तक अध्ययन से बच्चों के पठन कौशल, शब्दावली, भाषा ज्ञान, कल्पनाशक्ति और समझने की क्षमता में सुधार हो रहा है। किताबों के माध्यम से बच्चों की दोस्ती बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर, आनंददायक और अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। शिक्षकों

के अनुसार पुस्तक पढ़ने की आदत बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। **बांकी, कटिया और धर्मनगर में दिख रहा उसाह** विकासखंड बलरामपुर के प्राथमिक विद्यालय बांकी, प्राथमिक विद्यालय कटिया एवं प्राथमिक विद्यालय धर्मनगर में छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी और स्टडी कॉर्नर का उत्साहपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। बच्चों में पुस्तकों के प्रति बढ़ती उत्सुकता और नियमित अध्ययन की आदत विद्यालयों में विकसित हो रही सकारात्मक शैक्षिक संस्कृति को दर्शाती है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय बच्चों को पढ़ने, समझने, सोचने और स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल लाइब्रेरी एवं लर्निंग कॉर्नर इस दिशा में प्रभावी माध्यम साबित हो रहे हैं। किताबों से बच्चों की दोस्ती बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर, आनंददायक और प्रभावी बनाने की दिशा में विद्यालयों में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्नाव में 200 युवाओं को मिलेगा हुनर, छह माह की ट्रेनिंग के बाद रोजगार की तैयारी

उन्नाव। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बंधर के पास एक चमड़ा फैक्ट्री परिसर में शुक्रवार को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक शिशिर अवस्थी ने बताया कि हिंदुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी) की ओर से प्रेरश में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उन्नाव में लेदर कट और जरी-जर्दोजी ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोनों ट्रेडों में कुल 200 युवाओं का नामांकन हुआ है और प्रशिक्षण की अवधि छह माह निर्धारित की गई है।

ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, दोनों पैर कटे दिल्ली नौकरी के लिए निकला था

उन्नाव। उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार रात ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान आसीवन थाना क्षेत्र के जवा खेड़ा गांव निवासी कुलदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय रामबिलास के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, कुलदीप गुरुवार रात दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह दिल्ली में निजी नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास वह अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और परिजनों को घटना

की सूचना दी। शुक्रवार सुबह परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने बताया कि कुलदीप परिवार में सबसे बड़ा था और दिल्ली में निजी नौकरी कर परिवार का खर्च चलाता था। वह तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ा था। कुलदीप की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। माता-पिता और भाई-बहनों का रो-रोकर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, कुलदीप की पहचान आसीवन थाना क्षेत्र के जवा खेड़ा गांव निवासी कुलदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय रामबिलास के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, कुलदीप गुरुवार रात दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह दिल्ली में निजी नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास वह अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और परिजनों को घटना

मिशन शक्ति के तहत पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बांसी (सिद्धार्थनगर)। मिशन शक्ति के तहत शुक्रवार को थाना शिवनगर डिंडी पुलिस ने प्राथमिक विद्यालय कड़सरा में महिला सशक्तिकरण हेतु बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर छात्र-छात्राओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेंद्र सिंह के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष बृजेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपनिरीक्षक रामधनी प्रसाद एवं महिला कांस्टेबल शालिनी वर्मा ने छात्र-



निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। एंटी रोमियो अभियान के तहत डिंडी चौराहे पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को छात्राओं को गुड़ टच-बैड टच के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष,

नौ लाख रुपये की लागत से गांधी आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में बनेगा शौचालय



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। गांधी आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में विद्यार्थियों एवं कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत नौ लाख रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरी ने विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। विदित हो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने खेल मैदान में विद्यार्थियों

चोरी के आभूषण और नकदी समेत आरोपित गिरफ्तार

देवरिया। जनपद की बघौचघाट पुलिस और एंटी थेफ्ट टीम ने चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए रहमत शाह (30) को रामपुर महुआबारी चौराहे के पास ईंट-भट्टे के समीप से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से सैमसंग का मोबाइल बरामद किया।

उसकी निशानदेही पर घर से चोरी के आभूषण और 1,100 रुपये नकद भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता ने बताया था कि परिवार के साथ बाहर जाने के बाद लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और आलमारी व बक्से से आभूषण तथा नकदी चोरी थी। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 317(2) बढ़ाई गई है।

